पांचवीं योजना में जिस कार्यक्रम पर मुख्य रूप से बल दिया गया है वह समाज के पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधारना है । विभिन्न आवास योजनाओं और कार्यक्रमों के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिये विभिन्न निष्पादन अभिकरणों द्वारा मकानों का निर्माण करके और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने के बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आरम्भ करके इसे पूरा करने का प्रयास किया जाता है । आवास स्थलों के आवंटन के लिये पात्र लगभग 112 लाख परिवारों में से 31 मार्च, 1977 तक 71.06 लाख परिवारों को आवास स्थलों का आवंटन किया जा चुका था ।

राजस्थान के थार मरुस्थल का विकास

1857. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने राजस्थान के थार रेगिस्तान के विकास के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) इस क्षेत्र में अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है तथा इस क्षेत्र में कितनी मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन होने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). वर्तमान पद्धति के अनुसार, केन्द्रीय सहायता विशिष्ठ परियोजनाओं, योजनाओं से जुड़ी हुई नहीं है यह राज्यों को उनकी अपनी-अपनी वार्षिक योजनाओं के लिए एक मुश्त धनराशि के रूप में दी जाती है जोकि 70 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में वंटित की जाती है । इस तरह, केन्द्र द्वारा राजस्थान में थार रेगिस्तान के विकास हेतु विशेष रूप से दी गई केन्द्रीय सहायता का पता लगाना सम्भव नहीं है ।

रेगिस्तान का कठोर क्रोड क्षेत्र राजस्थान के 11 जिलों में है अर्थात बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, चुरु, जोधपुर, जालोर, पाली, झुनझुनु (चिरावा तथा झुनझुनु तहसीलें) गंगानगर तथा सिकार । चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, राजस्थान में रेगिस्तानी इलाकों के विकास हेतु प्रायोगिक परियोजनाएं जिनमें वनरोपण, भू-संरक्षण, घास के मैदानों का विकास, चरागाह विकास की योजनाएं शामिल है, बाड़मेर तथा जैसलमेर के जिलों में 117.25 लाख रुपए की अनुमानित लागत से आरम्भ की गई थीं । इसके अलावा, राजस्थान के सूखाग्रस्त तथा रेगिस्तानी जिलों में मध्यम तथा लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, वनरोपण, ग्रामीण संचार आदि जैसे श्रम प्रधान कार्यों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 14.43 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे ।

पहले पैरा में उल्लिखित 11 जिलों में से, पहले 9 जिलों की सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत इन जिलों को केन्द्र तथा राज्य द्वारा बराबर-बराबर अंशदान के आधार पर कुल 39.90 करोड़ रुपए का आवंटन दिए जाने की संभावना है । कार्यक्रम को नया रूप दिया गया है और यह कृषि, पशु तथा डेरी विकास, वनरोपण, सिंचाई तथा भूगत जल उपयोग, ग्रामीण, विद्युतिकरण तथा पेयजल आपूर्ति जैसे

क्षेत्रों में धन लगाकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों के संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करेगा, आय तथा रोजगार के अवसर बढ़ायेगा तथा उन्हें स्थिर करेगा, और यहां तक सम्भव होगा, पारिस्थिति संतुलन को बनाये रखेगा। यह कार्यक्रम आगे चलकर अभाव की स्थितियों को कम करने में सहायता करेगा। यद्यपि सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम इन जिलों में चल रहा है, तो भी यह रेगिस्तानी इलाकों की विकास आवश्यकताओं के केवल कुछ भाग से ही सम्बन्ध रखता है। पांचवीं योजना में रेगिस्तान विकास के लिए कोई योजना शामिल नहीं की गई थी। तथापि, योजना आयोग न केवल राजस्थान बल्कि हरियाणा तथा गुजरात के निकटवर्ती राज्यों के लिए भी रेगिस्तानी इलाकों के समग्र विकास की सम्पूर्ण नीति पर विचार कर रहा है और वर्तमान सरकार ने 17.6.77 को लोक सभा में पेश किए गए चालू वर्ष के बजट में रेगिस्तान विकास के लिए 6.10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

थार रेगिस्तान विकास से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण उपायों में ये शामिल है :—

(i) राजस्थान नहर क्षेत्र में विश्व बैंक साहायियत परियोजना के भाग के रूप में चलाया जा रहा वनरोपण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की मुख्य मदें ये है —रेत के टीलों का स्थिरीकरण, नहर तट के पास सुरक्षा-घेरा वृक्षारोपण, सड़क के किनारे वृक्षारोपण तथा चरागाह विकास। पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए राजस्थान नहर क्षेत्र के वनरोपण की एक योजना अनुमोदित की गई थी। वर्ष 1974–75 के दौरान 950 हेक्टेयर में वनरोपण कार्य तथा 3000 हेक्टेयर में चरागाह विकास कार्य के लिए 28.71 लाख रुपए की धनराशि व्यय की गई थी। वर्ष 1975–76 के दौरान 2000 हक्टेयर में वनरोपण कार्य करने तथा 7000 हेक्टेयर में चरागाह विकास करने के लिए 64.42 लाख रुप की धनराशि मंजूर की गई थी। वर्ष 1976–77 के लिए 2006 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य आरम्भ करने तथा 9000 हेक्टेयर में चरागाह विकास करने के लिए 105.30 लाख रुपए का प्रस्ताव था। वर्ष 1977–78 के लिए कार्यक्रम हेतु अनुमोदित धनराशि 164.50 लाख रुपए है। ये विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित भौतिक लक्ष्यों के अनुसार है। यह सूचित किया गया है कि राज्य ने 1976–77 में लगभग 87 लाख पेड़ उगाए तथा लगाए और उनका वर्ष 1977–78 में 115 लाख पेड़ लगाने का प्रस्ताव है।

(ii) पश्चिमी राजस्थान में राजस्थान नहर का निर्माण : राजस्थान नहर परियोजना से राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर तथा चुरु के रेगिस्तानी जिलों में 13 लाख हैक्टेयर खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सिचाई आपूर्तियां प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। इसमें 3·1 लाख हैक्टेयर की उठाऊ सिंचाई (60 मीटर की उठान तक) शामिल है। वर्ष 1975–76 के दौरान 288,380 हैक्टेयर क्षेत्र को सींचा गया है और 1976–77 के दौरान (फरवरी 1977 तक) सिंचित क्षेत्र 261,831 हेक्टेयर है। राज थान नहर परियोजना की अनुमानत लागत 396 करोड़ रुपए है अर्थात् सोपान —176 करोड़ रुपए तथा सोपान II—220 करोड़ रुपए। फरवरी, 1977 के अंत तक 161.37 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

(iii) राजस्थान नहर कमांड क्षेत्र विकास परियोजना : जुलाई 1974 में राजस्थान नहर कमांड क्षेत्र विकास परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन के साथ हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह समझौता दिसम्बर, 1974 में लागू हुआ था। इस परियोजना के अन्तर्गत

अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन 6 वर्षों की अवधि में निष्पादित की जाने वाली कुल 174 मिलियन डालर की अनुमानित लागत में 83 मिलियन डालर का उधार देगी। परियोजना का कार्यान्वयन जुलाई, 1974 से ही शुरु हो गया था।

इस परियोजना में शाखा, वितरिका तथा छोटी नहरों की रेखाएं खींचना, सड़कों का निर्माण, वनरोपण, ग्राम जल आपूर्ति तथा आन-फार्म विकास शामिल है। राजस्थान नहर की कमांड क्षेत्र विकास परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान ऋण नीचे दिए गए है :

(लाख रुपए में)

	अनुदान	ऋण
1974–75	76.55	——
1975–76	——	——
1976–77	55.00	75.00
	131.55*	75.00

*इसमें राजस्थान भूमि विकास निगम की इक्विटी पूंजी में मंजूर की गई धनराशि शामिल नहीं है।

(iv) थार रेगिस्तानी इलाके में डेरी-उद्योग : थार रेगिस्तान में अथवा उसके आसपास दो डेरी योजनाएं हैं। ये दोनों योजनाएं जोधपुर तथा बीकानेर में स्थित हैं, इनमें प्रत्येक की प्रतिदिन एक लाख लीटर दूध की उत्पादन क्षमता है। इन परियोजनाओं जो प्रचालन वाढ़ कार्यक्रम में शामिल की गई हैं के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को दुधारु पशु खरीदने के लिए ऋण दिए जाते हैं। इसके अलावा, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न निवश कार्यक्रम उपलब्ध किए जा रहे हैं

राजस्थान राज्य के 11 रेगिस्तानी जिलों में वर्ष 1974–75 के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 11.590 लाख मीटरी टन तथा 1975–76 में 29.605 लाख मीटरी टन था। वर्ष 1976–77 की इसी प्रकार की सूचना अभी तक उत्पलब्ध नहीं हुई है।

Quality of Cereals supplied through Ration Shops

1858. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints that the cereals supplied through ration shops are of poor quality and are generally adulterated with stones and dust;

(b) whether Government have investigated such complaints; and

(c) if so, the steps taken to supply reasonably good quality to the consumers?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). There have been some complaints from time to time about the quality of cereals issued by the ration shops. All complaints are investigated invariably. To safeguard the interest of the consumers, samples of foodgrains are displayed at the ration shops; foodgrains which are found to be sub-standard, are replaced; ration shops are inspected from time to time to check the quality of cereals in stock with them for issue.